भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3031
11.03.2026 को उत्तर देने के लिए

क्षमता विकास (सीडी) योजना

3031.श्री सुरेश कुमार कश्यपः
श्री योगेन्द्र चांदोलियाः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्षमता विकास (सीडी) योजना के अंतर्गत अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत आर्थिक गणना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सांख्यिकीय क्षमता, आंकड़ों की गुणवत्ता और समयबद्धता पर उक्त योजना के प्रभाव का कोई आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने डेटा की गुणवत्ता, समयबद्धता और डिजिटल प्रसार में सुधार के माध्यम से भारत की सांख्यिकी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण करने में क्षमता विकास (सीडी) योजना के तहत महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। सीडी योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:
कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू (सीएपीआई) के उपयोग के माध्यम से सर्वेक्षण प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण किया गया, जिसे ई-सिग्मा प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया, जिसमें अंतर्निहित सत्यापन जांच, एआई-सक्षम चैटबॉट और बहुभाषी इंटरफेस शामिल हैं, जिसके परिणामस्वरूप सर्वेक्षण परिणामों को जारी करने में तेजी आई। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) और गैर-निगमित क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसयूएसई) जैसे प्रमुख सर्वेक्षणों के लिए प्रतिदर्श डिजाइन को मासिक और तिमाही अनुमान तैयार करने के लिए बढ़ाया गया था। प्रमुख मैक्रोइकॉनॉमिक संकेतकों, अर्थात् सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आधार वर्ष संशोधित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, एमओएसपीआई की नई वेबसाइट, गोस्टेटस मोबाइल एप्लिकेशन, ई-सांख्यिकी पोर्टल, माइक्रोडाटा पोर्टल और डेटा आदान-प्रदान के लिए एपीआई के उपयोग के माध्यम से डेटा प्रसार और पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। एमओएसपीआई ने 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत वाली चल रही केंद्रीय क्षेत्र की अवसंरचना परियोजनाओं की स्थिति की निगरानी के लिए पैमाना (परियोजना मूल्यांकन अवसंरचना निगरानी और राष्ट्र निर्माण के लिए विश्लेषण) नामक एक नई वेब आधारित निगरानी प्रणाली भी शुरू की है। एमओएसपीआई ने डेटा उपयोगकर्ता सम्मेलनों, परामर्शों, कार्यशालाओं और प्रतिक्रिया तंत्रों के माध्यम से हितधारकों की सहभागिता को भी सुदृढ़ किया है और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दिया है।

एमओएसपीआई ने व्यापक डेटा सामंजस्य/मानकीकरण पहल की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय मेटाडेटा संरचना (एनएमडीएस 2.0) को अपनाना, सांख्यिकीय गुणवत्ता मूल्यांकन ढांचा (एसक्यूएएफ) शुरू करना, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण मानकों के साथ संरेखण शामिल है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी (एनएसएसटीए), जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान है, नियमित रूप से "आधिकारिक सांख्यिकी और संबंधित क्षेत्रों" पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है, जिनमें डिजिटल उपकरण, डेटा विश्लेषण और डेटा प्रबंधन शामिल हैं। ये कार्यक्रम केंद्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के सांख्यिकी कर्मियों की क्षमता निर्माण के लिए हैं, ताकि क्षेत्र से बेहतर डेटा संग्रह सुनिश्चित किया जा सके।

सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण सहायता (एसएसएस) उप-योजना के तहत, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को सांख्यिकी क्षमता और संचालन को सुदृढ़ करने/सुधारने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

(ख) एमओएसपीआई ने आठवीं आर्थिक गणना (ईसी) के संचालन के लिए पहल की है और यह एमओएसपीआई की क्षमता विकास योजना को जारी रखने के लिए ईएफसी की प्रस्ताव का एक हिस्सा है।

(ग) और (घ) क्षमता विकास (सीडी) योजना का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन अध्ययन अगस्त, 2025 से नवंबर, 2025 के दौरान आयोजित किया गया है। मूल्यांकन रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यह योजना सांख्यिकीय क्षमता को सुदृढ़ करने, एसडीजी निगरानी का समर्थन करने और समय पर और विश्वसनीय डेटा प्रसार सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है और सीडी योजना को इसकी वर्तमान अवधि से आगे जारी रखने की संस्तुति की गई है।

****